मोदी के 'अच्छे दिनों' का आगाज़

मनोज केमार झा

मोदी सरकार को देश की सत्ता संभाले अभी जुमा-जुमा आठ रोज ही हुए थे कि इसकी चाल दिखाई पड़ने लगी। चेहरा तो पहले से ही बेनक़ाब था और चरित्र भी जाहिर है।

ग़ौरतलब बात ये है कि भ्रष्टाचार और घोटालों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की बात करने वाले मोदी के मंत्रिमंडल में एक से बढ़कर एक भ्रष्ट घोटाले बाज और भ्रष्टाचारी हैं। एक शख्स तो ऐसा है जिस पर बलात्कार और यौनशोषण के आरोप हैं। पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को लीजिए। क्या मोदी को पता नहीं कि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप के कारण ही पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। इनके अलावा भी कितने मगरमच्छ भरे पड़े हैं। नाम गिनाना व्यर्थ होगा। सबों को पता है, पर अब भाजपा वालों की भी मजबूरी है मोदी, क्योंकि प्रधामंत्री पद के लिये उनका चुनाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। संघ के ख़िलाफ़ भाजपा में कौन जा सकता हैभला! भाजपा को पहली बार केन्द्र की सत्ता में लाने वाले रामरथी आडवाणी की जो दुर्गति संघ-विरोध के कारण हुई, उसे सबने देखा। जब उनकी नहीं चली तो किसकी चलती। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मोदी के मातहत काम करने को मजबूर हैं। आडवाणी को भरोसा है राष्ट्रपति पद का। यह भरोसा उन्हें बार-बार दिलाया जा रहा है।

बहरहाल, बजटपूर्व रेल यात्री भाड़ा और माल भाड़ा में भारी बढ़ोत्तरी कर उन्होंने यह साफ इशारा कर दिया है कि लोग़ों के लिये बहुप्रचरित 'अच्छे दिन' का मतलब क्या होने जा रहा है। साफ शब्दों में यह सरकार कांग्रेस नीत यूपीए सरकार से दसगुना महंगाई बहुत जल्दी बढ़ाएगीऔर दसगुना बीसगुने में जल्दी बदलेगा। भाजपा नेताओं ने साफ़ शब्दों में कहा है कि देश के विकास के लिए जनता महंगाईभुगतने को तैयार रहे। बिना महंगाई बढ़ाए देश का विकास नहीं हो सकता। अभी गैस और डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाऐंगे, ताकि अंबानियों-अडानियों को विशुद्ध और प्रचुर लाभ हो। सरकार के लिये उनका भुगतान सबसे जरूरी है, नहीं तो उनका भरोसा सरकार पर नहीं रहेगा। जनता-जनार्दन का भरोसा भले सरकार पर न रहे, नरेन्द्र मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता; लेकिन अंबानियों-अडानियों का भरोसा उन पर से उठ गया तो उनकी कुर्सी डांवाडोल हो सकती है। इसलिए, स्वयं मोदी सरकार के हित में महंगाई का बढ़ाया जाना

निहायत ही जरूरी हो गया है। खास बात तो ये है कि कांग्रेस नीत पूर्व यूपीए सरकार के राज में भी महंगाई के मारे लोग़ बेदम थे और वो भी रोज-ब रोज महंगाई बढ़ा कर ही अपने आप को बचाए रखने की जुगत कर रही थी और जब तक सत्ता में थी तो बिना किसी की परवाह किए डंके की चोट पर शासन करती रही। सभी पार्टियों के बड़े-बड़े कद्दावर नेता सोनिया से मिलकर फ़ख्र महसूस करते थे। कई क्षत्रपों की नकेल सोनिया के हाथ में थी। मुलायम से लेकर मायावती और लालू तक जाल में फंसे हुए थे। वामपंथियों ने भी काफ़ी समय तक सोनिया-मनमोहन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का साथ दे खूब सत्ता की मलाई चाटी और साथ छोड़ते ही राजनीति के बियाबान में गुम हो गए। कोई नामलेवा न रहा।

इधर, कांग्रेस और यूपीए में शामिल दलों के मंत्रियों ने निर्द्वंद्व भाव एक से एक ऐसे घोटाले किए, जिनका वर्ल्ड रिकार्ड है। फिर भी इस सत्ता को कोई चुनौती नहीं थी, अगर चुनाव न होते।

विकल्प के अभाव में त्रस्त जनता में पस्त हिम्मती के साथ बेचारेपन का भाव ही ज़्यादा उभरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस जनतांत्रिक ढांचे का जो स्वरूप है, उसमें जन के लिये व्यवस्था संचालन में कोई जगह कहां है। उसका महत्त्व एक वोटर के रूप में कहीं ज्यादा है। गौर करने की बात ये है कि इन चुनावों में मज़दूरों-किसानों मेहनतकश अवाम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। चुनावों के दौरान मोदी फोबिया पैदा किया गया। एक उन्माद जो निराशोन्माद में भी बदल सकता है।

सवाल ये है कि वर्तमान मोदी सरकार पूर्व कांग्रेसनीत सरकार से किस रूप में भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, जब रेल यात्री और माल भाड़े में वृद्धि का विरोध हुआ तो सरकार की ओर से ये जवाब आया कि यह फैसला पूर्व सरकार का था और उसने सिर्फ़ लागू किया है। दलील घाटे का। रेलवे में ऊपर से लेकर नीचे तक किस हद तक भ्रष्टाचार और लूट व्याप्त है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना, न करना। भाड़ा बढ़ाने से लूट का अनुपात भी बढ़ जाता है। पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल का हाल सबको मालूम है। मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने से पूरी तरह से जड़ जमा चुके तंत्र में कोई बदलाव कैसे हो सकता है और दूसरी बात, मोदी भी उसी व्यवस्था के उग्र पैरोकार हैं जहां 'ऐंटीलिया' का विकास होता है, जहां अंबानी-अडानी और उनकी जी-हुजूरी में पलने वालों का विकास होता है, उच्च मध्यमवर्ग का विकास होता है और आम जनता अविकास के भंवर में पड़ के रह जाती है। ऊपर से महंगाई की मार। जीना मुहाल। मोदी सौ शहरों के विकास की बात करते हैं, गांवों के विकास का कोई एजेंडा सामने नहीं। हां, जिन शहरों के बिकास का सपना मोदी देख रहे हैं, तो ज्यादातर शहर किसी न किसी थैलीशाह की जागीर ही होंगे और उजड़े हुए गांवों से आने वाले बेशुमार नंगे-भूखे-वंचित बेचारे लोग़ों की नारकीय झुग्गी बस्तियां होंगी। इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए बहुलांश आबादी का वंचित और बेचारा रहना जरूरी है, तभी देश में मोदी का गुजरात मॉडल वस्तुत: साकार हो सकेगा।

भारत जैसे देशों में विकास और अविकास का उपरोक्त मॉडल ही है। कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं। न कोई राजनीतिक विकल्प। वर्तमान विश्वव्यवस्था में आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संकट विकासशील भारत में ही नहीं, अमेरिका, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में भी घनीभूत होकर सामने आता रहा है। लूटमार, कर्ज, दान, भीख, से व्यवस्था का एक हद तक निर्वाह हो रहा है। चूंकि प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर भी कोई कानूनी रोक नहीं है, इसलिए जन की वंचना बढ़ती ही जाती है और अस्तित्व की रक्षा के लिए परिस्थितियां गुलामी तय कर देती हैं।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी के पास कोई ऐसी योजना ही नहीं है, जो उनकी पूर्ववर्त्ती सरकारों से भिन्न हो। हां, मोदी कॉरपारेट को इस हद तक छूट अवश्य दे सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का नामोनिशां भी मिट जाए। उल्लेखनीय है कि ओएनजीसी (ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन) ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह शिकायत दर्ज कराई है कि गोदावरी बेसिन में मुकेश अंबानी की गैस कंपनी की गतिविधियों से उसे हज़ारो करोड़ का नुकसान हुआ है। कोयला भारी लूट का क्षेत्र है। गैस महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा। स्वयं अंबानी ने घोषणा की है महंगाई बढ़ने की। पता नहीं, किस हैसियत से की। शायद स्वयं को किंगमेकर समझते हों।

बहरहाल, मोदी सरकार की खास बात ये हो सकती है कि किसी बात पर ज्यादा सोचना-समझना व्यर्थ है, मामला बिजनेस का है और अपने फ़ायदे का हो तो पास करो। पूंजीपतियों का विकास ही देश का विकास है। ये ही बुलेट ट्रेन लाएंगे। बुलेट की गति से विकास के लिए जनता एक शाम भूखी रहे, दो रोटी कम खाए, चाहे जो करे, विकास किसी कीमत पर होगा। बहुसंख्यक जनता का विकास होगा जूठन पर, जो सोनिया-मनमोहन सरकार का भी नीति-निर्देशक सिद्धांत था।

बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना रहा है कि कांग्रेस और भाजपा ने ले-देकर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का चरित्र जनद्रोही है। दोनों ही साम्प्रदायिक हैं।

भाजपा हिंदू साम्प्रदायिकता भड़काती है तो अन्य दल अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हैं। साम्प्रदायिकता सत्ताधारियों का प्रमुख औजार औपनिवेशिक काल से ही रही है। अंग्रेजों ने ब्रह्मास्त्र की तरह इसका उपयोग कर स्वतंत्रता के साथ भारत को विभाजन की भी सौगात दी थी, जिसे विश्व की बड़ी त्रासदियों में एक माना जाता है। इसका नासूर अभी भी बना हुआ है। धार्मिक पहचान को उभार कर समुदायों के बीच घृणा फैलाना, दंगे करवाना, जिहाद चलवाना, साम्राज्यवादी अभी भी अपना प्रमुख अस्त्र मानते हैं।

भाजपा जहां खुले तौर पर हिंदू साम्प्रदायिक विचारधारा को स्वीकार करती है, वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजनसमाज पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) एवं चुनाव बाज वामपंथी दल भी छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी हैं। ये सबके लिए समानता की जगह अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीतिक गठजोड़ कायम करते हैं।

मोदी सरकार की एक खासियत यह भी उभर कर सामने आने वाली है कि राजनीतिक निर्णयों पर कॉरपोरेट-देशी और विदेशी हावी रहेगा। मंत्रालय परोक्ष रूप से कॉरपोरेट दिग्गज ही चलाएंगे और पब्लिक सेक्टर के आधारभूत ढांचे को धीरे-धीरे नीलाम कर दिया जाएगा। इससे आम जनता की वंचना और बेचारगी ज्यादा बढ़ेगी, पर उसके पास छटपटा के रह जाने के सिवा और विकल्प ही क्या है?

जनप्रतिरोध का कोई वैचारिक-सांगठनिक स्वरूप उभरता दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता। सुधारवादी राजनीतिक हस्तक्षेप जाहिर है, निरर्थक साबित होगा। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी वाले राजनीतिक प्रयोग से यह साबित हुआ है।

अब मोदी अपने मन की चलाते हैं, यानी अपने कॉरपोरेट आकाओं के मन की तो उन्हें रोकेगा कौन? क्या नीतीश-लालू-मुलायम-ममता-वाम गठबंधन। क्या इनके साथ मिलके कांग्रेस। यह शायद ही संभव हो और हो भी तो इस आम जनता के वंचित तबकों को क्या फ़ायदा? क्या मोदी की जगह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन भी सत्ता में आ जाए तो वह शोषण और लूट की स्थापित परंपरा पर नहीं चलेगा?

उसका भी तो मॉडल वही है। राजनीतिक दिवालियापन या कहें जनता को नारों से भरमाने की परिपाटी ऐसी है कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताते हैं तो कुछ लोग नीतीश कुमार के विकास के बिहार मॉडल की बात करते हैं।

ध्यान रहे, मोदी ने अपनी जीत को भारत की जीत बताया था। और 'गंगा मैया ने बुलाया है' कह कर बहुसंख्यक हिंदू जनता की धार्मिक भावनाओं को उभार कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी। उन्होंने कई दांव आजमाए थे जो सफल रहे।

ऐसे में, मोदी राज आने वाले दिनों में जनता के लिए और कौन-कौन-सी सौगात पेश करेगा, इसका इंतज़ार किया जाना चाहिए।

मछली बाजार

परजीविओं पर चुप्पी : शोर करने के बहाने कई!

अशरफ़

तय है कि मोदी सरकार कांग्रेसी राज्यपालों को हटाकर राजभवनों में अपने यानी भाजपाई राज्यपालों को बिठाएगी। तो क्या? परजीवी राजनेताओं का एक नया समूह परजीवी राजनेताओं के पुराने समूह की जगह ले लेगा। बस इतना ही। जैसे पहले सोनिया और कांग्रेस ने अपने स्वामिभक्तों को उपकृत किया था, वही अब मोदी और भाजपा करने जा रहे हैं। जैसे जनता पहलेवालों का बोझा उठाने को मजबूर थी वैसे ही नयों को भी उसे भुगतना होगा। न जानेवाले राज्यपाल जनता के किसी काम के थे और न आने वाले होंगे।

इन राज्यपालों में से अधिकांश, लाट साहबी ऐय्याशियों के साथ-साथ भ्रष्टाचार में भी जम कर लगे होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी राज्यपाल बी. एल. जोशी को लीजिये जिन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति में पैसा एकमात्र मानक बना रखा था। या उत्तराखंड के भाजपाई सुदर्शन का समय याद कीजिये जिन्होंने एक एन जी ओ बनाकर राज्य के हर पैसेवाले की गर्दन पकड़कर वसूली की थी। इनमें शीला दीक्षित (केरल), नारायणन (पश्चिम बंगाल), वांचू (गोआ) जैसे भी हैं जिनका नाम बड़े घोटालों में चल रहा है। हरियाणा के पहाड़िया हैं जो छोटे-मोटे हाथ अपने ए डी सी की मार्फत मारते रहते हैं।

मीडिया में राज्यपालों के फेरबदल को लेकर शोर कुछ इस तरह मचाया गया जैसे इस कवायद में कोई सचमुच में जनहित का पेंच फंसा है। जबकि बहस होनी चाहिए थी कि इस पद के संवैधानिक दायित्व को देखते हुए नियुक्ति के मानक तय किये जाएं और नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाय। साथ ही इन पदों पर होनेवाले खर्च की सीमा भी तय की जाय ताकि लोकतंत्र के पिछले दरवाजे से काबिज इन मुफ्तखोरों की ऐय्याशियों पर कुछ तो लगाम लग सके।

परजीविता को लेकर कार्पोरेट मीडिया की असली चुप्पी तब सामने आती है जब मामला उनके अपने आकाओं की सरेआम मुनाफाखोरी को बल देने का हो। बढ़ती मंहगाई, रेल भाड़े में वृद्धि और बिजली की कमी को लेकर मीडिया ने लगातार कई दिनों तक जमीन आसमान एक कर के रखा। इस बीच मोदी सरकार क्या करती रही? चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर आम आदमी के लिए चीनी के दाम बढ़ा दिए गए। साथ ही आटोमोबाइल क्षेत्र को दी गयी मनमोहन सरकार की एक्साइज छूट को और छह महीने के लिए बढ़ाकर कारों, बाइकों इत्यादि को सस्ता

पुराना दस्तूर है कि संकट शासक पैदा करते हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इराक में आतंकी गृह-युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के छिट-पुट बढ़े दाम की आड़ लेकर तमाम सरकारों के चहेते अम्बानी समूह की गैस के दाम बढाने की घोषणाएं शुरू हो गईं। कायदे से, जनता के हितों के प्रति सावधान मीडिया को तो मोदी से पूछना चाहिए कि जब अम्बानी की यह गैस भारत में ही पैदा हो रही है और इसकी यहीं खपत होनी है तो इसका इराक के हालात से क्या वास्ता! पर तमाम समाचारपत्रों और टी वी चैनलों में अम्बानी के स्वामित्व के चलते मीडिया की मुहिम लोगों को गैस की बढ़ी कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने की है। तुरंत नहीं तो तीन-चार माह बाद सही, जनता पर यह बोझा आना ही है।

रखने का रास्ता पुख्ता किया गया। न सिर्फ मीडिया ने यह सब नजरअंदाज किया बल्कि वह अच्छी सुविधा के तर्क को प्रचारित कर रेल भाड़े में वृद्धि पर जन-आक्रोश को भी भोंथरा करता रहा।

हद तो यह है कि दिल्ली में बिजली संकट का इस्तेमाल बिजली के दाम बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और कार्पोरेट मीडिया बगल से ताली बजा रहा है। जबकि केंद्र की तीन लाख तैंतीस हजार करोड़ की अटकी पड़ी बिजली परियोजनाएं वर्षों पीछे चल रही हैं। यहाँ तक कि सरकारी बैंकों ने इन पर जो पैंसठ हजार करोड़ का कर्ज दे रखा है, उसके डूबने की भी आशंका है। इसी तरह चीनी मिल मालिकों को चौवालीस सौ करोड़ का ऋण इस बात का मुहैय्या कराया जा रहा है ताकि वे गन्ना किसानों का वर्षों से पड़ा बकाया चुकता कर सकें। यानी जिन मिल मालिकों को किसानों से धोखाधड़ी के लिए जेल भेजना चाहिए था उन्हें ही अब किसानों को भुगतान के नाम पर मुंहमांगी धनराशि मोदी सरकार दे रही है।

पुराना दस्तूर है कि संकट शासक पैदा करते हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इराक में आतंकी गृह-युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के छिट-पुट बढ़े दाम की आड़ लेकर तमाम सरकारों के चहेते अम्बानी समूह की गैस के दाम बढाने की घोषणाएं शुरू हो गईं। कायदे से, जनता के हितों के प्रति सावधान मीडिया को तो मोदी से पूछना चाहिए कि जब अम्बानी की यह गैस भारत में ही पैदा हो रही है और इसकी यहीं खपत होनी है तो इसका इराक के हालात से क्या वास्ता! पर तमाम समाचारपत्रों और टी वी चैनलों में अम्बानी के स्वामित्व के चलते मीडिया की मुहिम लोगों को गैस की बढ़ी कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने की है। तुरंत नहीं तो तीन-चार माह बाद सही, जनता पर यह बोझा आना ही है। टाइम्स आफ इण्डिया का तर्क है कि कांग्रेसी तो कीमत चार डालर से बढ़ाकर आठ डालर से भी अधिक करने जा रहे थे, भाजपा सरकार शायद सात डालर से कम रखे। वाह, क्या रियायत है! शुक्रिया टाइम्स आफ इण्डिया।

मीडिया की व्यावसायिकता किसी भी सीमा तक जा सकती है। ए बी पी न्यूज ने बदायूं के बलात्कार-हत्या काण्ड के सन्दर्भ में कई दिनों तक उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को स्त्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर घेरे रखा। अंतत: अखिलेश सरकार की ओर से करोड़ों रुपये का विज्ञापन इस चैनल को दिए जाने पर वह घेरेबंदी उठा ली गयी है।